



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, शनिवार, चैत्र 17, 1976/चैत्र 28, 1898

No. 79]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1976/CHAITRA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th April, 1976

SUBJECT:—Setting up of a High-Level Study Team to study the problems of Coir Industry.

No. 25(30)/75-C&S.—Coir Industry is an important cottage industry providing employment to about 5 lakh workers. Kerala which produces about 70 per cent of coconuts accounts for about 90 per cent of coir production in India. States other than Kerala have immense potential for the development of unretted coir/fibre. The progress and problems of coir industry were reviewed in some details by a Study Group set up by the Planning Commission in 1969. A number of important and far reaching developments have taken place since then. The Coconut Husk Control Order 1973 was issued by the Central Government under the Essential Commodities Act; during the years 1974 and 1975, the Govt. of Kerala issued a number of Orders under the Defence of India Rules for the regulation

of movements/price etc., of coir/coir goods. A number of representations were received by the Government from time to time from the trade, exporters, workers etc. on the various problems confronting the industry. For the development of coir industry, the State Governments have suitable plan outlays in their State Five Year Plans. The Reserve Bank of India has since made suitable arrangements for the refinancing of coir cooperatives, specially Kerala State. For a limited period and as a special case, the Central Government have been providing special Central assistance to the Govt. of Kerala for restructuring the existing potentially viable coir cooperatives in that State. In the meanwhile, the volume of export of coir/coir goods have been continuously on the decline. The need for modernisation of the industry was emphasised in some quarters. All these developments necessitate an urgent review and study of the industry in depth.

2. Considering, therefore, the importance of coir industry and the complexities of its problems, Government have decided to constitute a High-level Study Team to study the problems of coir industry. The Study Team will consist of the following :

Chairman

1. Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission

Members

2. Shri A. P. V. Krishnan, Additional Secretary, and Integrated Financial Adviser, Ministry of Industry & Civil Supplies.
3. Joint Secretary (In-charge of Coir) Ministry of Industry & Civil Supplies.
4. Shri K. Madhava Das, Chief Officer, Reserve Bank of India, Agricultural Credit Department, Bombay.
5. A Senior Officer representing the Government of Kerala.
6. A Senior Officer representing the Ministry of Commerce

Member-Secretary

7. Chairman, Coir Board, Cochin.
3. The terms of reference shall be:—
 - I. To make a critical review of the progress of Coir Industry in Kerala and other coir producing States and Union Territories over the last three years with particular reference to—
 - (i) availability of husk and its utilisation for production of 'white' and 'brown' fibres, yarn and other products, and the production techniques adopted;
 - (ii) marketing of the products within and outside the country;
 - (iii) working of coir cooperatives;
 - (iv) utilisation of outlays in the public sector and institutional finance.
 - II. To suggest suitable measures for overcoming the present problems and for a rapid and healthy development of industry over the remaining years of the Plan period with particular reference to the processes/items of manufacture which may be mechanised in a phased manner, the programmes to be undertaken by the State Governments and the Centre including the Coir Board and the role of the financial institutions for ensuring fuller utilisation of husk and yarn and increasing internal sales, exports etc.

4. The Study Team will submit its report as expeditiously as possible but in any case by 30th June 1976.

ORDER

Ordered that the Resolution shall be published in the Gazette of India.

Ordered also that copies of the Resolution shall be sent to all concerned.

A. K. RAY,
Commissioner (IC).

उद्योग और नागरिक पुर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1976

विषय : कयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय अध्ययन दल का गठन करना ।

सं० 25(30)/75-सो०एच एस०.—कयर उद्योग एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है । भारत में होने वाले कुल कयर उत्पादन में केरल जहां नारियल की करीब 70% पैदावार होती है का भाग 90% है । केरल के अलावा अन्य राज्यों में भी अनरेटेड कयर फाइबर के विकास के लिए पर्याप्त विभव है । कयर उद्योग की प्रगति और समस्याओं की योजना आयोग द्वारा 1969 में गठित एक अध्ययन दल द्वारा कुछ विस्तार से संवीक्षा की गई थी । तब से अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन हुए हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 1974 और 1975 में दी कोकोनट हस्क नियंत्रण आदेश, 1972 जारि किया गया था । केरल सरकार ने क्या कयर/कयर वस्तुओं का लाना ले जाना मूल्य आदि के विनियमित करने के लिए भारत रक्षा नियमों के अधीन अनेक आदेश जारी किये हैं । समय समय पर व्यापारियों/निर्यातकों, कर्मचारियों आदि से उद्योग की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कयर उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों ने अपने राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में उचित योजना परिव्यय का प्रावधान किया है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कयर सहकारी समितियों विशेष करके केरल राज्य की कयर सहकारी समितियों के पुनर्वितीयन के लिए उपयुक्त व्यवस्था की है । एक समिति अवधि के लिए और एक विशेष प्रकरण के रूप में केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को उस राज्य में विद्यमान जीव्यधम कयर सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देती रही है । इस दौरान कयर/कयर वस्तुओं का निर्यात निरन्तर गिरता रहा है । कुछ क्षेत्रों में उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था । इन सभी स्थितियों से इस उद्योग का और गहराई से अध्ययन तथा तत्काल समीक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है ।

2. अतः कयर उद्योग के महत्व तथा इसकी समस्याओं की जटिलता को देखते हुए सरकार ने कयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन करने का निर्णय किया है । अध्ययन दल का गठन निम्न प्रकार होगा ।

अध्यक्ष

1. श्री बी० शिवरामन,
सदस्य,
योजना आयोग ।

सदस्य

2. श्री ए० पी० बी० कृष्णन्
अवर सचिव और इन्टीग्रेटेड वित्तीय सलाहकार,
उद्योग और नागरिक पुर्ति मंत्रालय ।
3. संयुक्त सचिव (कयर के प्रभारी)
उद्योग और नागरिक पुर्ति मंत्रालय ।

सदस्य

4. श्री के. माधव दास,
मुख्य अधिकारी,
रिजर्व बैंक आफ इंडिया,
कृषि ऋण विभाग,
बम्बई ।
5. केरल सरकार का प्रतिनिधि
एक वरिष्ठ अधिकारी ।
6. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला
एक वरिष्ठ अधिकारी ।

सदस्य सचिव

7. अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोचीन ।

3. इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

I. केरल में तथा अन्य कयर उत्पादक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में हुई कयर उद्योग की प्रगति की निम्नलिखित संदर्भ में गुण-वोध परक समीक्षा करना :

- (1) “सकेद” और “सूरे” फाइबर यार्न और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए हस्क की उपलब्धता और उसका उपयोग तथा अपनाई गई उत्पादन तकनीक;
- (2) उत्पादों की देश के भीतर और बाहर बिक्री;
- (3) कयर सहकारी समितियों का कार्यकरण;
- (4) सरकारी क्षेत्र और मंस्थगत वित्त का उपयोग;

II. उद्योग की विद्यमान समस्याओं से पार पाने और योजनावधि के बाकी वर्षों में उद्योग के प्रोत्थ और स्वस्थ विकास के लिए प्राक्स्थाप्य कार्यक्रम के अनुसार यंत्रीकृत की जाने वाली प्रक्रियाओं और उत्पादन की वस्तुओं, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और कयर बोर्ड द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा हस्क और रेशों का पूर्णतम उपयोग सुनिश्चित करने के मामले में वित्तीय संस्थानों की भूमिका और आन्तरिक बिक्री नियंत्रण आदि की वृद्धि करने के विशेष संदर्भ में अभ्युपाय सुझाना ।

4. अध्ययन दल अपनी रिपोर्टें यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत करेगा किन्तु हर हालत में 30 जून 1976 तक प्रस्तुत कर देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी सम्बन्धित लोगों को भेजी जायें ।

श्रवनी कान्त राय,

आयुक्त (औद्योगिक सहकारिता) ।